बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 268

वास्तविक हो बजट

बजट की रूपरेखा तैयार करते वक्त किसी भी वित्त मंत्री को सबसे पहले आगामी वर्ष में अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर तय करनी होती है। राजस्व, घाटा तथा तमाम अन्य आंकड़े इस बात पर निर्भर करते हैं कि सरकार उक्त वृद्धि दर का कितना सटीक आकलन लगा पाती है। उदाहरण के लिए चालू वर्ष में यदि मुद्रास्फीति समेत जीडीपी वृद्धि दर (नॉमिनल) का अनुमान सही होता तो राजस्व आकलन में कुछ गंभीर खामियों से बचा जा सकता था।

सही अनुमान अतीत के रुझानों के सही अध्ययन पर निर्भर करता है। सन 2020 तक के दशक में अर्थव्यवस्था कमोबेश दोगुनी हो गई। इस दौरान औसत वृद्धि दर 7 फीसदी की रही। परंतु दशक के बीच के वर्षों में अर्थव्यवस्था को तेल कीमतों में भारी गिरावट से भी लाभ मिला। यह शायद दोहराया न जाए। इसके अलावा मौजूदा वैश्विक आर्थिक हालात भी बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था में कई सुधार करने की आवश्यकता है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, निर्यात में ठहराव है, राजकोषीय या मौद्रिक नीति पहल की कोई खास गुंजाइश नहीं है। बीती तिमाही में चूंकि अर्थव्यवस्था का गैर सरकारी हिस्सा 3 फीसदी की गति से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा, ऐसे में अर्थव्यवस्था के लिए अगले वर्ष के लिए 5 फीसदी के आसपास की अनुमानित वृद्धि दर ही वास्तविक होगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा आधा फीसदी का बदलाव हो सकता है।

बीते दशक में 7 फीसदी की वृद्धि हासिल करने वाली तथा उससे पिछले दशक में और तेजी हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत अच्छी दर नहीं है। परंतु हमारे सामने जिस तरह के कठिन विकल्प हैं, उन्हें देखते हुए धीमी वृद्धि को स्वीकार करने के सिवा चारा नहीं है। फिलवक्त तो 7 फीसदी की दर से विकसित होती अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजस्व अनुमान लगाया भी नहीं जा सकता। ऐसे में हकीकत का सामना करना ही बेहतर है। खासतौर पर तब जबकि बात बजट की तैयारी की हो। बजट में घाटे के आंकड़े को काफी कम करके बताया गया है। यह कमी जीडीपी के 2 फीसदी तक है। हर बजट में संसाधनों की सीमा होती है लेकिन आने वाले बजट में यह संकट भी चरम पर होगा।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

बजट से इतर देखें तो मध्यम अवधि में पूर्वानुमान काफी उलझाऊ है। खासकर तब जबकि वृद्धि दर को 7 फीसदी के वांछित स्तर पर लौटने में समय लगे। वित्त मंत्री को अपने बजट भाषण में यह साफ करना चाहिए कि वह 7 फीसदी की दर कैसे हासिल करेंगी। उन्हें धीमी होती अर्थव्यवस्था के गतिशील होने तक हकीकत को अपनाने के लिए वह क्या कदम उठाने जा रही हैं उनके बारे में भी उन्हें सूचित करना चाहिए। सरकारी कदमों के बारे में अनुमान लगाया जा सके तो यह हमेशा बेहतर होता है।

राजस्व में कमी होने पर तलवार व्यय पर गिरेगी, भले ही मंदी के मध्य अर्थशास्त्री ऐसी सलाह नहीं दें। यह बात अहम है कि बजट अनुशासन नजर आए। ऐसे में आवंटन को मौजूदा स्तर पर बरकरार रखना होगा। जो पैसा व्यय न हो वह समाप्त हो जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक सार्वजनिक निवेश हो चुका है, उनसे कहा जाना चाहिए कि वे प्रदर्शन में सुधार दर्शाएं। उदाहरण के लिए रेलवे का राजस्व, राजमार्ग टोल, उच्च बिजली टैरिफ आदि। यदि वित्त मंत्री कड़ी निगाह डालें तो उन्हें और अधिक गैर कर राजस्व की राह निकालने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए सरकारी बैंकों के लिए नई पूंजी जुटाने के लिए उनमें से एक या दो का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। इसका बोझ करदाताओं पर नहीं डालना चाहिए।

सबसे बढ़कर बजट को आधुनिक बनाने का वक्त आ गया है। सबसे पहले नकद अंकेक्षण से संग्रहण अंकेक्षण की ओर बढ़ना चाहिए ताकि उन बिलों को शामिल किया जा सके जो बकाया हैं लेकिन चुकता नहीं हैं। इसी प्रकार सरकार को बैलेंस शीट से इतर मुद्दों की जानकारी देनी चाहिए जो अब तक बजट का हिस्सा नहीं हैं। इसे ऐसी खबरें आनी बंद होंगी जिनमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा छिपे हुए व्यय पर सवाल उठाया जाता है। मिसाल के तौर पर सरकारी कंपनियों द्वारा बैंकों से पैसे उधार लेकर खाद्य सब्सिडी बिल चुकाना या रेलवे संस्थानों से अग्रिम भुगतान लेना ताकि रेलवे के खाते में घाटा न दिखे। अधिक विश्वसनीय आंकड़े बेहतर होंगे और इससे सरकारी कामकाज की पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

बिनय सिन्हा

वित्तीय मजबूती की राह पर चीन निरंतर अग्रसर

विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला चीन मुद्रा के क्षेत्र में कई ऐसे कदम उठा रहा है जिनसे लगता है कि भविष्य उसके ही नाम होगा। विस्तार से बता रहे हैं **श्याम सरन**

चीन जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। फिलहाल उसकी अर्थव्यवस्था का आकार 14 लाख करोड़ डॉलर है, जो विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 18 प्रतिशत है। वर्ष 2013 से यह दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी देश रहा है और इसका मौजूदा आयात-निर्यात का कुल आंकड़ा 4.5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक है। इतना ही नहीं, चीन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर एवं बॉन्ड बाजार भी है। इसका बॉन्ड बाजार 13 लाख डॉलर का है और दुनिया के बॉन्ड बाजार में इसकी हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है। इसी तरह, इसका शेयर बाजार पूंजीकरण वैश्विक आंकड़े का करीब 12 प्रतिशत है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन का रुतबा इसके वित्तीय आंकड़ों में नहीं झलकता है।

वैश्विक स्तर पर लेनदेन के माध्यम के रूप में चीन की मुद्रा की हिस्सेदारी 2018 में कम होकर 15 प्रतिशत से कम रह गई है, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 25 प्रतिशत तक हुआ करता था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल भुगतान में केवल 2 प्रतिशत ही रेनमिनबी के जरिये होता है। 2016 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लाख करोड़ डॉलर मूल्य के स्पेशल ड्रॉइंग राइट (एसडीआर) में अमेरिकी डॉलर, यूरोपीय क्षेत्र की मुद्रा यूरो, जापानी मुद्रा येन और ब्रिटेन के पाउंड के साथ रेनमिनबी भी सुरक्षित मुद्रा के रूप में शामिल थी। रेनमिनबी का भारांश एसडीआर में 10.86 प्रतिशत दिया गया था। आईएमएफ के सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में रेनमिनबी की मात्रा अधिकतम 1 लाख डॉलर तक हो सकती है, लेकिन फिलहाल यह महज 194 अरब डॉलर ही है। चीन ने 30 देशों के साथ मुद्रा अदला-बदली (करेंसी स्वैप) का समझौता कर रखा है और इसका मूल्यांकन फिलहाल 500 अरब डॉलर है। हालांकि इसका इस्तेमाल मामूली स्तर तक ही हुआ है। रेनमिनबी दुनिया की दूसरी शीर्ष मुद्राओं की तरह विश्वसनीयता अर्जित करने में असफल रही है। पूंजी प्रवाह पर नियंत्रण समाप्त करने और मुद्रा में उतार-चढ़ाव झेलने से चीन के इनकार करने से आगे की प्रगति अब तक थमी है।

युआन के अंतरराष्ट्रीयकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चीन ने अब एक अलग रणनीति तैयार की है। अपनी मुद्रा को अपेक्षित स्थान दिलाने के लिए चीन अपने बॉन्ड एवं शेयर बाजार के बड़े आकार का इस्तेमाल करते हुए इन्हें वैश्विक वित्तीय बाजारों से जोड़ रहा है। शुरू में चीन ने अपने शेयरों में कोटा आधारित कारोबार की अनुमति देने के लिए हॉन्ग कॉन्ग, शांघाई और हॉन्ग कॉन्ग शेनझेन स्टॉक कनेक्ट स्थापित किया और कोटा को उदार बनाया और फंडों के स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल बना दी। इसने अपना बॉन्ड बाजार विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की और पहले रेनमिनबी में जारी बॉन्ड हॉन्ग कॉन्ग और बाद में सिंगापुर, ताइवान और लंदन में उतारे।

प्रमुख वैश्विक सूचकांकों में चीन के शेयर एवं बॉन्ड को शामिल किया जाना उत्साहजनक है। शांघाई एवं शेनझेन स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले चीन के ए-शेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट और एमएसएसीआई ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किए गए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट बॉन्ड (सीजीबी) अब ब्लूमबर्ग बार्कलेज ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल हैं और जल्द ही एफटीएसई का हिस्सा हो सकते हैं। निवेश कंपनी स्क्रोडर्स का दावा है कि आम तौर पर सूचकांकों से जुड़े फंडों में निवेश करने वाले अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशक से रकम का प्रवाह शुरू में सालाना 200 अरब डॉलर होगा, जो बाद में बढ़कर सालाना 400 अरब डॉलर तक हो जाएगा।

चीन के शेयर एवं बॉन्ड बाजारों का तेजी से विस्तार हो रहा है और खुदरा निवेशकों ने भी इनमें बढ़-चढ़ कर निवेश शुरू कर दिया है, ऐसे में रकम का प्रवाह लाखों करोड़ों डॉलर में रह सकता है। यह ध्यान रहे कि केवल सीजीबी ही अब तक शामिल किए गए हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड के शामिल होने में भी अधिक देर नहीं है। स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स को चीन में रेटिंग एजेंसी के तौर पर काम करने की अनुमति मिल चुकी है। अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों के लिहाज से कॉर्पोरेट बॉन्ड को रेटिंग मिलने से उनके लिए वैश्विक सूचकांकों में शामिल होना आसान हो जाएगा और इससे चीन के बॉन्ड बाजार में रकम का प्रवाह भी बढ़ेगा। शांघाई में युआन आधारित तेल वायदा एक्सचेंज की स्थापना से भी चीन की मुद्रा की हैसियत बढ़ रही है। शांघाई इस साल दुबई को पछाड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल वायदा बाजार बन गया है।

चीन के यूनियनपे क्रेडिट कार्ड का अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजार में रुतबा बढ़ा रहा है। दुनिया में जारी कुल क्रेडिट कार्ड में यूनियनपे की हिस्सेदारी 58 प्रतिशत है और इस समय करीब 7.6 अरब यूनियनपे क्रेडिट कार्ड धारक हैं। यह क्रेडिट कार्ड 174 देशों में स्वीकार होता है। हरेक साल चीन के लोग 15 करोड़ विदेशी यात्राएं करते हैं और पर्यटन पर हरेक साल होने वाले कुल खर्च में इनका हिस्सा 20 प्रतिशत है। इस वजह से दुनिया के कारोबारी प्रतिष्ठान यूनियनपे क्रेडिट कार्ड से भुगतान ले रहे हैं।

चीन ने 2015 में क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (सीआईपीएस) शुरू किया था, जो ब्रसल्स स्थित स्विफ्ट की तर्ज तैयार किया गया है। इस समय सीआईपीएस स्विफ्ट के साथ सहयोग कर रहा है, लेकिन चीन का वास्तविक लक्ष्य एक वैकल्पिक वैश्विक भुगतान एवं निपटान प्रणाली के तौर पर इसे (सीआईपीएस) स्थापित करना है। सीआईपीएस में 12 अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ 31 साझेदार हैं, इसके साथ ही 745 परोक्ष रूप से इसमें भागीदार निभाते हैं। 2018 में सीआईपीएस ने चीन से बाहर युआन में 755 अरब डॉलर के लेनदेन का निपटान किया। हालांकि स्विफ्ट के मुकाबले यह न के बराबर है, लेकिन इसके जरिये निपटान तेजी से बढ़ रहा है। स्विफ्ट प्रतिदिन 6 लाख करोड़ डॉलर का निपटान करता है। सीआईपीएस के इस्तेमाल को अमेरिका के कदमों से भी बढ़ावा मिला रहा है, जो रूस और ईरान जैसे देशों को बाहर रखने के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल करता है। रूस ने अपना सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मेसेजेज स्थापित किया है, जो यूरेशियन इकनॉमिक यूनियन देशों में काम करती है और चीन के बैंक इसमें शिरकत करते हैं। ऐसी खबर आ रही है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत, चीन और रूस त्रिपक्षीय भुगतान प्रणाली विकसित करने पर विचार कर रहे हैं, जो स्विफ्ट से स्वतंत्र होकर काम करेगी।

चीन ब्लॉकचेन तकनीक आधारित संप्रभु डिजिटल करेंसी लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस बारे में अभी विस्तार से कोई सूचना नहीं है। चीन में इस समय होने वाले कुल लेनदेन में 70 प्रतिशत से अधिक डिजिटल माध्यम से होते हैं, इसलिए सॉवरिन डिजिटल करेंसी की दिशा में काम करना कोई हैरत की बात नहीं। एक 'एशियाई युआन' बनाने के लिए इसे एक दूसरी समानांतर योजना से जोड़ा जा रहा है। चीन के अर्थशास्त्री सन मिन्गाकी इस रणनीति का खुलासा कुछ इस तरह करते हैं, 'हॉन्ग कॉन्ग डॉलर और न्यू ताइवान डॉलर को आंतरिक स्तर पर जोड़कर 'ग्रेटर चाइना रेनमिनिबी तैयार करना लघु अवधि का लक्ष्य है। मध्यम अवधि में जापान की येन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के वोन और दूसरी एशियाई देशों की मुद्रा के सहयोग से 'एशियाई युआन' प्रणाली अस्तित्व में लाने का लक्ष्य है। इससे अमेरिकी डॉलर, यूरो और एशियाई युआन वैश्विक मुद्रा प्रणाली के तहत त्रिकोणीय व्यवस्था के रूप में काम करेगी।' कुल मिलाकर अंतिम लक्ष्य प्रत्येक देश की आर्थिक ताकत एवं उसके कारोबार मूल्यांकन के आधार पर एक आदर्श, डिजिटल एवं विकेंद्रीकृत या गैर-सॉवरिन वैश्विक मुद्रा प्रणाली स्थापित करना है। अब सवाल उठता है कि अगर चीन ने डिजिटल करेंसी के साथ कदम आगे बढ़ा दिए हैं तो यह लक्ष्य प्राप्त होने के बाद भविष्य किसके नाम होगा? इन घटनाक्रम के बीच भारत कहां खड़ा होता है, जो इस समय अपनी कुछ परेशानियों से जूझ रहा है?

(लेखक पूर्व विदेश सचिव और सीपीआर में सीनियर फेलो हैं।)

दलित उत्थान के लिए चंद्रशेखर आजाद से 'रावण' तक का सफर

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

इस बात में थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि मायावती और अन्य लोग उनके नाम का उल्लेख करने पर भौंह सिकोड़ लेते हैं। हालिया आंदोलन ने रावण की शरिक्सयत को मजबूत किया है

जिस समय दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ आवाज उठ रही थी तो एक व्यक्ति पुलिस के साथ लुकाछिपी का खेल खेल रहा था। खुद को रावण नाम देने वाले चंद्रशेखर भी यह लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका जन्म सहारनपुर के धड़कूलि गांव में एक चमार परिवार में हुआ था। चंद्रशेखर ने पास के ही छुटमलपुर गांव में ठाकुरों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने दलितों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को महसूस किया और इससे लड़ने की ठानी। आंबेडकरवादी और कांशी राम से प्रभावित (लेकिन मायावती की तरह नहीं) चंद्रशेखर ने दलितों को संगठित करने के लिए कांशी राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा, अफसरशाही और आत्मरक्षा के तरीके आजमाए। उन्होंने भीम आर्मी का गठन किया और जाति तथा महिला-पुरुष के भेदभाव से परे सभी को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सहारनपुर जिले में 400 भीम आर्मी स्कूल खोले। उन्होंने आत्मरक्षा की कक्षाएं चलाना शुरू किया और गांवों में घूम-घूम कर बाइक रैलियां कीं। इन गांवों में ऊंची जाति वाले ठाकुरों के गांव भी शामिल थे। वे इसे अपने मजबूत होते वजूद को दिखाने के सांकेतिक तरीके के तौर पर देखते थे।

यह काफी जरूरी है। लोध जाति से ताल्लुक रखने वाली और बाद में केंद्रीय मंत्री बनीं साध्वी उमा भारती एक पुरानी घटना के बारे में बताती हैं कि उनके गांव टीकमपुर में उनकी जाति के दूसरे लोग ठाकुर परिवारों के घरों के आगे से साइकिल चलाकर नहीं जा सकते थे। उन्हें साइकिल से उतरकर पैदल चलना होता था क्योंकि ठाकुर इसे अपना अपमान मानते थे। यह 25 साल पहले की बात है। हालांकि आज भी कुछ नहीं बदला। भीम आर्मी ने 18 साल से अधिक उम्र के दलितों को संगठन से जुड़ने का आह्वान किया। इसके ज्यादातर सदस्य चमार समुदाय या इसकी उपजाति जाटव से संबंधित हैं। लेकिन भीम आर्मी ने मुसलमानों का भी समर्थन किया। हालांकि संगठन का किसी तरह का औपचारिक ढांचा नहीं है और यह गैर-पंजीकृत संस्था है लेकिन दावा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इसके 20,000 से ज्यादा सदस्य हैं। संगठन का ज्यादातर ध्यान प्रत्यक्ष तरीके से मदद करके दलितों की गरिमा का संरक्षण और उसका बचाव करना है। हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में आजाद ने कहा, 'भीम आर्मी की मदद से दलित युवाओं को पता चला कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और वे अब उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीम आर्मी किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि दलितों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है।'

साल 2015 में उस समय रावण की परेशानी शुरू होने लगी जब उन्होंने अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया। इसमें लिखा था, 'धड़कूलि गांव के चमार आपका स्वागत करते हैं।' जिस गांव में ठाकुर रहते हों वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? ठाकुरों ने इस पर काली स्याही पोत दी। अब यह तनाव सीधी लड़ाई में तब्दील हो गया और उस दौरान शीर्ष पर पहुंच गया जब भाजपा ने बिना मंजूरी लिए सहारनपुर के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में 'शोभा यात्रा' निकाली। कुछ सप्ताह बाद राजपूत राजा महाराणा प्रताप की जयंती पर दलित-ठाकुर टकराव हो गया। राज्य सरकार ने हिंसा भड़काने के लिए भीम आर्मी को जिम्मेदार ठहराया। रावण ने दावा किया कि सरकार इस आंदोलन को दबाने और ऊंची जाति के लोगों को संरक्षण देने के लिए उन्हें निशाना बना रही थी। राज्य प्रशासन ने रावण को गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायालय में पहुंचा और उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनको दोबारा गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों के भारी विरोध के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया था लेकिन इस दबाव के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया। जब वह जेल (और अस्पताल) में थे तो प्रियंका गांधी ने टेलीफोन पर बात की थी। आजाद अघोषित तौर पर कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने लगे।

सहारनपुर दलितों के लिए आवाज उठाने और मुसलमानों तथा दलितों के बीच एकता के लिए जाना जाता है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पहल का समर्थन किया। लोकप्रिय लेखक और दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद के अनुसार, 'करीब 400 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दलित और मुस्लिम कुल मतदाताओं के 30 प्रतिशत हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 90-95 प्रतिशत दलित और मुसलमान घरों से बाहर निकलकर मतदान करते हैं। इसलिए अगर वे साथ आते हैं तो चुनाव की दृष्टि से अहम हो जाएंगे। मेरा मानना है कि दलितों और मुसलमानों, खासकर युवाओं में एक साथ आने को लेकर काफी उत्सुकता है।' रावण इस एकता का चेहरा बनकर उभरे हैं हालांकि देश के दूसरे हिस्सों में अधिक लोग उन्हें नहीं जानते। जिस दौर में बसपा की चुनावी जमीन लगभग समाप्त हो गई हो और भाजपा दलितों को लामबंद करने में जुटी हो, ऐसे में भीम आर्मी दलित समुदाय में से प्रतिरोध का प्रतीक बनकर उभरी है। प्रख्यात दलित विद्वान आनंद तेलतुम्बडे लिखते हैं कि इसकी उत्पत्ति को वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स से जोड़कर देखा जा सकता है जो भारत की तत्कालीन दिवालिया राजनीति का नतीजा था।

इस बात में थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि मायावती और अन्य लोग उनके नाम का उल्लेख करने पर भौंह सिकोड़ लेते हैं। हालिया आंदोलन ने रावण की शख्सियत को मजबूत किया है।

कानाफूसी

समांतर मार्च

कोलकाता में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अध्यापक ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध में आयोजित रैली में हिस्सा लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के डीन प्रदीप बसु एनआरसी और सीएए की कॉपी जलाने के नारे लगा रहे हैं। उन्हें फासीवादी सरकार को हटाने की बात कहते हुए भी सुना जा सकता है। बसु ने कहा कि प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय से श्याम बाजार तक चार किलोमीटर लंबा यह मार्च स्वत: स्फूर्त था और किसी राजनीतिक दल या छात्र संगठन का झंडा देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि विरोध करने की जरूरत महसूस हो रही थी और छात्रों ने संपर्क किया तो वह तैयार हो गए।

मशविरों का दौर

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सन 2020 के बजट को लेकर आंतरिक मशविरे की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। पार्टी की कोशिश यह है कि वह बजट निर्माण के पहले सभी संबद्ध लोगों से संपर्क करे और उस बातचीत से निकला फीडबैक मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दे। पार्टी ने इस कवायद का जिम्मा संगठन महासचिव बी एल संतोष को सौंपा है। पार्टी के आर्थिक मामलों के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने पिछले दिनों कहा कि ऐसे हर सुझाव का स्वागत है जो पार्टी और सरकार को जमीनी हकीकतों से रूबरू कराए। मशविरे की प्रक्रिया गत 19 दिसंबर को आरंभ हुई और यह 14 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में 11 चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। इन मशविरों की रिपोर्ट को भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा से चर्चा के बाद सरकार को भेज दिया जाएगा।

आपका पक्ष

जैविक खेती को मिले बढ़ावा

फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक से खेती करना जरूरी है, क्योंकि इससे किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है। देश के किसान अब आधुनिक तकनीक से खेती करने लगे हैं। अगर विज्ञान का उचित प्रयोग किया जाए तो मनुष्य के लिए यह वरदान साबित हो सकती है लेकिन इसके अनुचित प्रयोग से अभिशाप भी बन सकती है। कुछ किसान फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी फसल को जब कोई किसी रूप में सेवन करता है तब उस पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फल, सब्जियों की पैदावार या इसके भंडारण में जिन रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा है वे भी शरीर के लिए हानिकारक है। ये जानलेवा बीमारियों को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे। अगर

समय रहते रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का प्रयोग नहीं किया गया तो अनाज सेहत का दुश्मन बन जाएगा। जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष योजनाएं लाने के साथ किसानों को तकनीकी मदद देनी होगी। किसानों को पशुपालन के

खेतों में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर सरकार को रोक लगानी चाहिए

प्रति जागरूकता के लिए नई नीति बनानी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

गरीबों की पहुंच से दूर होता प्याज

प्याज एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका उपयोग सामान्य लोग करते हैं। यह खासकर गरीबों के लिए एक सब्जी की तरह है जिससे वे रोटी के साथ खा लेते हैं। पिछले महीनों में प्याज के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और यह गरीब की पहुंच से बाहर हो चुका है। प्याज के दाम में कमी लाने के लिए सरकार विदेशों से इसका आयात कर रही है जिसकी कीमत 50 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे में प्याज की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे इसकी कीमतों में कमी आ सके।

घेवरचंद गोदीका, जयपुर

मांग आपूर्ति में संतुलन हो

वस्तु हो या सेवा अगर मांग और आपूर्ति के असंतुलन को समझ कर कारोबार करें तो यह सभी के हित में होगा। इससे रोजगार की कमी नहीं होगी और न ही उत्पादित वस्तुओं की बिक्री में कमी आएगी। जहां मांग और आपूर्ति का आकलन नहीं किया गया वहां कारोबारी संकट में आ जाते हैं। उन्हें या तो इन्वेंट्री की समस्या घेरती है या फिर उन्हें आपूर्ति की समस्या से जूझना पड़ता है। अगर रेलवे की सवारी डिब्बों की बात करें तो पता चलेगा कि वह अत्यधिक है। एसी डिब्बों की मांग इतनी है कि अगले कुछ साल तीन शिफ्ट में निर्माण कार्य चलाया जाए फिर भी पूरी नहीं होगी। आगामी बजट में सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि रोजगार सृजन हो सके।

हिम्मत जोशी, नागपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।